संपादकीय जागरण

सोमवार, 8 जनवरी, 2018 : माघ कृष्ण 7 वि. 2074

जब निराश हों तब कोई निर्णय न करें

सुरक्षा पर मंथन

यह स्वाभाविक ही है कि पुलिस प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर विशेष चर्चा होगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा होना अपेक्षित भी है और आवश्यक भी, लेकिन देखना यह है कि इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य को सशक्त बनाए जाने पर कोई ठोस विचार-विमर्श होता है या नहीं। यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने के लिए जो उपाय आवश्यक हो चुके हैं उनकी पूर्ति होती हुई नहीं दिख रही है। आंतरिक सुरक्षा के तंत्र को सशक्त करने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से पुलिस सुधारों के नाम पर फौरी उपायों पर अमल होता ही अधिक दिख रहा है। यह एक तथ्य है कि मोदी सरकार जिन मोर्चों पर कुछ खास नहीं कर सकी है उनमें एक पुलिस सुधार भी है। यह ठीक है कि कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिस राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों की स्थिति एक जैसी ही नजर आती है।

चिंताजनक केवल यह नहीं है कि करीब-करीब एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर जो सात सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए थे उनकी अनदेखी हो रही है, बल्कि यह भी है कि पुलिस वर्तमान चुनौतियों के हिसाब से पर्याप्त प्रशिक्षण एवं संसाधनों से लैस भी नहीं है। स्थिति कितनी दयनीय है, यह इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में थाने बुनियादी सुविधाओं से भी लैस नहीं हैं। करीब दो सौ थाने तो ऐसे हैं जिनमें टेलीफोन की भी सुविधा नहीं है। हालांकि इस बात को सभी स्वीकार कर रहे हैं कि भारत में आबादी के अनुपात में पुलिस बल की संख्या कहीं अधिक कम है, लेकिन विडंबना यह है कि पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ रहे हैं। स्थिति इसलिए और अधिक खराब है, क्योंकि संख्या बल के अभाव से जूझ रही पुलिस को अपने तमाम कर्मी तथाकथित विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात करने पड़ रहे हैं। बेहतर हो कि पुलिस प्रमुखों के इस सम्मेलन में इस बात को महसूस किया जाए कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा की पहली कड़ी है और उसे सबल किए बिना कानून एवं व्यवस्था के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया जाए तो पुलिस के ढांचे में सुधार मुश्किल नहीं। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरों के रूप में केवल नक्सलवाद, आतंकवाद अथवा उग्रवाद सरीखे संकट ही नहीं हैं, बल्कि सामान्य कानून एवं व्यवस्था में गिरावट को लेकर आम जनता की बढ़ती चिंता भी है। यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पुलिस को एक सक्षम एवं आधुनिक बल के रूप में तब्दील करने की दिशा में आगे बढ़े। यह तब संभव है जब राजनीतिक दलों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि वे पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति छोड़ें।

कल्याणकारी योजनाएं

योगी सरकार गरीब परिवारों के लिए नई पेंशन योजना लाने जा रही है। इसका लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिन्हें किसी भी अन्य योजना में पेंशन नहीं मिल रही है। इसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कराया जायेगा। पेंशन की धनराशि 500 से एक हजार रुपये के बीच रखने की तैयारी है। इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में इसके लिए धन का प्रावधान कर दिया जायेगा।

दरअसल, सुशासन के अलावा सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोक कल्याण है। लोक कल्याण के वायदे करके ही राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार भी गरीबों के कल्याण के लिए समाजवादी पेंशन योजना चला रही थी। इस योजना के तहत प्रत्येक निर्धन परिवार की महिला को पांच सौ रुपये की पेंशन दी जा रही थी, किंतु अनियमितताओं का आरोप लगाकर मौजूदा सरकार ने इसे बंद कर दिया। इससे कई वास्तविक निर्धन परिवारों को झटका लगा। नई योजना में पात्रों का चयन किस तरह होगा, बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन गरीबी रेखा का पैमाना कारगर हो सकता है। इस पेंशन योजना को शुरू करने के साथ ही सरकार निर्धनों को 'गरीब कल्याण कार्ड' देने जा रही है। भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल इस वायदे को उसने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। इस कार्ड से गरीबों को सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निश्शुल्क इलाज मिलेगा। एक करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली, पानी व शौचालय की सुविधा से युक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए छह लाख रुपये तक का आवास ऋण रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही तेल, नमक, दाल व चीनी आदि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जायेंगी।

नई योजना में पात्रों का चयन किस तरह होगा, बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन गरीबी रेखा का पैमाना कारगर हो सकता है

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लालू यादव को सजा मिलने से राजद की राजनीतिक संभावनाएं प्रभावित होंगी?

आज का सवाल

क्या पाकिस्तान पर नकेल कसने को लेकर अमेरिका इस बार गंभीर नजर आ रहा है?

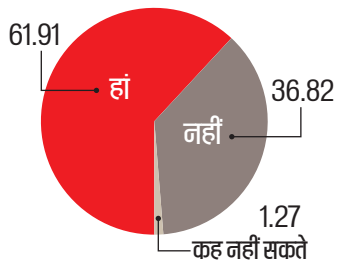

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बदलाव का वाहक बना नीति आयोग

अमिताभ कांत

आयोग ने न केवल अपने नाम के अनुरूप काम किया है, बल्कि भारत के कायाकल्प की कवायद को नई ऊर्जा, जोश और गतिशीलता भी प्रदान की है

वर्ष 2015 में स्थापित हुआ नीति आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे युवा संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना पुराने ढर्रे वाली केंद्रीकृत नियोजन वाली व्यवस्था को खत्म करके विकास एजेंडे को नई सोच देने के मकसद के साथ की गई थी। इसे सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने, विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने, विकास एजेंडे को पुनर्परिभाषित करने, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समाधान निकालने के लिए मंच प्रदान करने जैसे दयित्व दिए गए। इनके अलावा क्षमता निर्माण और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र की भूमिका निभाने जैसी महती जिम्मेदारियां भी इस नई नवेली संस्था को सौंपी गईं। अब चूंकि इस संस्था को अस्तित्व में आए हुए तीन साल बीत गए हैं तो आकलन करना उचित होगा कि क्या यह अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाया या फिर यह नई शैली में पुराने ढर्रे वाला ही संस्थान है। मेरी राय में तो आयोग अपनी भूमिका में पूरी तरह खरा उतरा और नीति निर्माण के मोर्चे पर व्यापक बदलावों का वाहक बना। पहला तो यही कि देश के नीतिगत परिदृश्य में आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को नई स्फूर्ति दी। विभिन्न मंचों पर परामर्श के बाद कई प्रमुख नीतिगत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तार्किक बनाने, कौशल विकास, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि विकास और डिजिटल भुगतान जैसे मसलों पर राज्यों के साथ चर्चा की गई। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 28 योजनाओं को चुस्त बनाया गया तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल की गईं और तमाम अन्य सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।

केंद्र और राज्यों की साझेदारी वाली योजनाएं शुरू की गईं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए मानव पूंजी कायाकल्प के लिए सतत योजना (एसएटीएच) जैसी पहल की गई तो बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों के लिए सतत सेवा सहयोग का आगाज हुआ। बेहतर उपचार सुविधाओं के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के अस्पतालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को हरी झंडी दिखाई गई। विशेष रूप से चिन्हित किए गए 115 जिलों का तकनीक और उपलब्ध सबसे बेहतर प्रक्रियाओं के जरिये कायाकल्प का काम शुरू हुआ तो देश में अंतरराज्यीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विचारों के माध्यम से एकता भाव बढ़ाने के लिए एक भारत-श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाया। कुछ विशेष योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ाया जो व्यवस्था पूर्ववर्ती योजना आयोग से एकदम अलग है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और डिजिटल कायाकल्प जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन और रैंकिंग की व्यवस्था की गई। बेहतर नतीजों के लिए उन्हें एक दूसरे से होड़ करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे नए और बेहतर तरीके अपनाकर शानदार परिणाम हासिल कर सकें। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने और केंद्र के साथ अटके मसलों पर समाधान निकालकर कानूनों को सुसंगत कर नियामकीय सुधारों के लिए भी राज्यों को पूरी मदद दी गई। नीति आयोग ने बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेहत सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके तहत अभी तक एयर इंडिया सहित 30 से अधिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी जा चुकी है तो खस्ताहाल और नुकसान में चल रहे 15 बीमारू उपक्रमों को बंद करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी आयोग ने व्यापक दृष्टिकोण और सतत विकास नजरिये के साथ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति के ढांचे की राह तैयार की तो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में दस द्वीपों के लिए द्वीप विकास एजेंसी यानी आइडीए की स्थापना की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीआइएस आधारित नियोजन का आगाज किया।

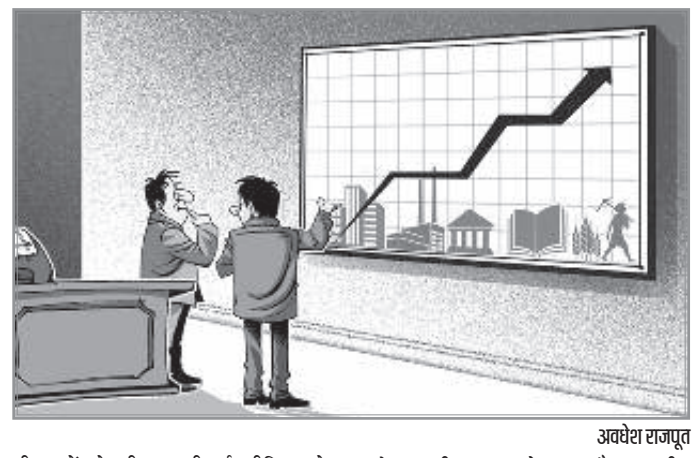

अवधेश राजपूत

स्वास्थ्य एवं कृषि दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां नीति आयोग ने पुरानी नियोजन प्रक्रिया के उलट क्रांतिकारी सुधारों का सूत्रपात किया। नीति आयोग द्वारा द्वारा तैयार किया नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक चिकित्सा शिक्षा में भारतीय चिकित्सा परिषद के पुराने ढर्रे वाली भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके नए युग का प्रवर्तन करेगा। इसी तरह आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य भी देश से कुपोषण को मिटाना है। पहले हुए सुधारों के लाभ से वंचित रहे कृषि क्षेत्र में भी अब बंटाईदारी, प्रशासन और विपणन जैसे मोर्चों पर सार्थक सुधार हो रहे हैं।

शासन के स्तर पर भी आमूलचूल बदलाव हो रहे हैं। इस दिशा में सरकारी योजनाओं को सक्षम बनाने के लिए आयोग ने सभी योजनाओं की निगरानी को संस्थागत रूप देने की पहल की है। विकास, निगरानी एवं आकलन कार्यालय इसी मकसद के लिए स्थापित किया गया है। उचित निगरानी समूची बजट प्रक्रिया का कायाकल्प कर देगी। नीति निर्माण में विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए समावेश जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके लिए 34 ज्ञान एवं शोध संस्थानों के साथ करार किए हैं। नीति व्याख्यान शृंखला के तहत वैश्विक बुद्धिजीवी और विचारक विभिन्न नीतिगत मसलों पर नीति निर्माताओं के साथ मंत्रणा कर शासन में नए विचारों और बहस को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह चैंपियन ऑफ चेंज पहल में युवा सीईओ और उद्यमी नीतिगत मसलों पर अपनी राय पेश करते हैं। प्रकाशनों में भी सभी राज्यों, क्षेत्रों के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और स्थानीय निकाय जैसे विषयों को स्थान दिया। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में अपनाए बेहतरीन तौर तरीकों की उचित समय पर जानकारी साझा करने के लिए रीयल टाइम नॉलेज पोर्टल शुरू किए जाने की तैयारी है। वहीं इंडिया एनर्जी पोर्टल जैसे मंचों से नीति आयोग सुशासन और इसके लिए बेहतरीन प्रक्रियाओं की जानकारी और शोध का उचित स्रोत बना है। उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए आयोग ने बड़े बदलाव किए। बहुप्रशंसित अटल इनोवेशन मिशन में बच्चों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए स्कूलों में प्रयोगशाला शुरू कीं तो अटल इनक्यूबेश सेंटर में स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं। वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन, 2017 के सफल आयोजन से भी आयोग ने दुनिया भर में अपनी सफलता का संदेश दिया। अब महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ शुरू किए जाने की भी तैयारी है।

अत्याधुनिक तकनीक अपनाने और उन्हें बढ़ावा देने में भी आयोग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसमें चाहे नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को विस्तार देने की बात हो या स्मार्ट शहरों में उपयुक्त तकनीक अपनाना। गुड़गांव-नोएडा के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी विचार जारी है। सुशासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की संभावनाएं भी तलाश रहा है। आंकड़ों की जरूरत पूरी करने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स पोर्टल बनाने की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में नीति आयोग ने न केवल अपने नाम के अनुरूप काम किया है, बल्कि भारत के कायाकल्प की कवायद को नई ऊर्जा, जोश और गतिशीलता भी प्रदान की है। यह भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने को तत्पर है।

(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं)

response@jagran.com

परिवार में छिपी किशोर अपराध की जड़

डॉ. विजय अग्रवाल

नाबालिगों के अपराध को परिवार एवं समाज द्वारा किए जाने वाले अपराध के रूप में देखा जाए। तभी कुछ हल निकल सकेगा

यह लेख लिखते समय अनायास ही चीन के आधुनिक साहित्य के महान कथाकार लू शून (1881-1936) की एक प्रसिद्ध कहानी 'एक पागल की डायरी' याद आ रही है। इस कहानी का नायक पागल कहता है, 'चार हजार साल से हम मनुष्य का गोश्त खाते आ रहे हैं। बच्चों ने उसे नहीं चखा है। बच्चों को बचाओ।' आज जब हम बच्चों को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त पाते हैं तो लगता है कि हमने लू शून की उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। और अब बच्चों ने भी आदमी का गोश्त चख लिया है। नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों ने पूरे देश के माथे पर लकीरें पांच साल पहले हुए निर्भया कांड के दौरान उकेरी थीं। 23 वर्षीय निर्भया के साथ की गई दरिंदगी में कुल जो छह लोग शामिल थे, उनमें एक 18 वर्ष से कम उम्र का भी था। उनमें से पांच को तो फांसी की सजा हो गई, लेकिन एक बच गया। इसके बाद नाबालिग की उम्र की सीमा 18 से घटाकर 16 करनी पड़ी। साथ ही कुछ दिनों पहले एक लड़के पर केस चलाने के मामले पर जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा कि चूंकि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है और वह इस अपराध के दंड को समझने के योग्य था, इसलिए उस पर मुकदमा वयस्कों की तरह ही चलेगा।

हाल में हुई कुछ अन्य अत्यंत दुखद घटनाओं से तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल के एक लड़के ने स्कूल के एक बच्चे की हत्या केवल इसलिए कर दी, ताकि कुछ दिनों के लिए परीक्षा टल जाए। नोएडा में तो एक लड़के ने अपनी मां और बहन को इसलिए मार डाला, क्योंकि वे उसे डांटते थे। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू हमें स्वयं के प्रति उनके द्वारा उठाए गए क्रूर कदमों में दिखाई देता है। नाबालिगों एवं युवाओं की आत्महत्या की खबरें आज आम हो गई हैं। 'ब्लू व्हेल' के खौफनाक खेल ने जघन्यता के उस नए स्वरूप को प्रस्तुत किया है जिसमें स्वयं के प्रति क्रूरता के विभिन्न चरण दिखाई देते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध कुल अपराध का लगभग एक प्रतिशत होते हैं। तीन साल पूर्व के लगभग 45 हजार बाल अपराधों में लगभग 30 हजार अपराध 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों द्वारा किए गए। राज्यसभा में बताया गया है कि इस तरह के अपराधों में पिछले पांच सालों में लगभग 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो बहुत चिंताजनक है। निर्भया कांड के बाद इस समस्या पर विमर्श के जो बिंदु सामने आए उनमें से अधिकांश का संबंध मुख्यतः इससे जुड़े कानूनों में सुधार और कठोर

दंड व्यवस्था से था। इनका अपनी जगह औचित्य है, लेकिन इसे ही पर्याप्त मान लेना एक बड़ी भूल होगी। इस समस्या की जड़ों की तलाश हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में करनी होगी। इसके लिए मैं अस्सी के दशक में राजकपूर की आई फिल्म 'बॉबी' के एक दृश्य की याद दिलाना चाहूंगा। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा धनी परिवार का एक नाबालिग बेटा जब अपने जन्मदिन पर घर लौटता है तो वहां पार्टी और सजावट तो खूब हैं, लेकिन उसके माता-पिता नहीं। वे अपने बेटे को 'एंज्वॉय' करने की बात कहकर स्वयं और कहीं चले जाते हैं। मां-बाप के इस व्यवहार से बेटा (ऋषि कपूर) अंदर से टूट जाता है और हताश होकर अपने एक निम्नवर्गीय परिचित के यहां चला जाता है, जहां उसकी भेंट बॉबी नाम की एक लड़की से होती है।

दरअसल इस छोटे से किंतु अत्यंत भावनात्मक दृश्य में बालमन की अनेक परतें और छवियां दिखाई देती हैं। आज माता-पिता के पास समय की कमी के कारण बच्चे निहायत ही एकाकी होते जा रहे हैं। एकल पारिवारिक संरचना ने बच्चों को बुजुर्गों की गोद, स्नेहयुक्त स्पर्श और मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियों से वंचित कर दिया है। इसके कारण उनमें संस्कारों और नैतिक मूल्यों का जबर्दस्त अभाव देखने में आ रहा है। यही स्थिति हमारी शिक्षा प्रणाली की भी है। फलस्वरूप हम उनसे जिस तरह के अनुशासन, मर्यादा एवं सहनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों की अपेक्षा करते हैं, वे विकसित नहीं हो पाते।

एक या दो बच्चों की नीति के कारण बच्चा स्वाभाविक रूप से परिवार का लाडला हो जाता है। इसके कारण उसके बिगड़ने की आशंका प्रबल हो जाती हैं। उसे घर के बाहर भी माहौल ऐसा नहीं मिलता, जहां से वह कुछ अच्छे गुण सीख सके। इससे उसके अंदर सामाजिकता की भावना पनप नहीं पाती। नगरों-महानगरों में खुले स्थानों के अभाव ने उसके खेल को इन्डोर एवं कंप्यूटर गेम की ओर धकेल दिया है। खेल के मैदान बच्चों में सहनशीलता तथा सामूहिकता की भावना विकसित करने के सर्वोत्तम एवं स्वाभाविक माध्यम होते हैं। ऐसे में सचिन तेंदुलकर की उस दिवस की प्रतीक्षा सचमुच मन को छू जाती है, जिस दिन माता-पिता अपने बच्चों से पढ़ाई करने के बजाय खेलने के बारे में पूछेंगे।

जो कुछ थोड़ा-बहुत बचा था, उन सबका सत्यानाश कर दिया इंटरनेट ने। यह भी धीरे-धीरे मादक पदार्थों की तरह एक नशे का रूप लेता जा रहा है। यही कारण है कि कई देशों ने बच्चों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। निःसंदेह इस पूंजीवादी व्यवस्था ने आज के बच्चों को जितना अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया है, वह उनके संस्कारों एवं मूल्यों के क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। करियर एवं जल्दी से सब कुछ पा लेने की अदम्य चाहत ने उन्हें अंदर से बेहद बेचैन और असंतुलित कर दिया है। इसी की परिणति हम साधनों की पवित्रता के पतन के रूप में देख रहे हैं।

कुल मिलाकर यह कि हमें इस बात को अच्छी तरह से समझकर खुलेमन से स्वीकार करना होगा कि कोई भी बच्चा अपराधी बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेता। आगे चलकर वह जो भी रूप धारण करता है, वह समाज के सांचे के अनुकूल होता है। इसलिए नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध को परिवार एवं समाज द्वारा किए जाने वाले अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। तभी इसका कुछ हल निकल सकेगा।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

करुणा

करुणा के बगैर जीवन एक पाखंड है। पीड़ित की आह बनकर करुणा हमें पुकारती है और उसे हम रसमय संगीत में तलाशते हैं। वृत्तियों का रिश्ता चित्त से होता है, किंतु करुणा शुद्ध हृदय से संबंधित है। लंबी साधना के बाद जब गौतम सिद्धार्थ के भीतर करुणा जगी तो वह भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध की साधना का लक्ष्य व्यक्तिगत निर्वाण न होकर सर्वगत कल्याण था। यही कारण है कि बुद्ध को 'अर्हत' की यात्रा रास नहीं आई और वे अनवरत साधना करते हुए 'बोधिसत्व' तक पहुंचे। विश्वकल्याण ही बोधिसत्व का निहितार्थ है। ऐसा व्यक्ति करुणा की जीवंत मूर्ति है। वह दुखियों की आह से द्रवित होकर कहता है कि संसार के सारे दुखों को मेरे भीतर उड़ेल दो ताकि सभी प्राणी इनसे मुक्त हो सकें। बुद्ध की करुणा किसी अलौकिक चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मविजय का प्रतिफल है। उनके भीतर करुणा की धारा फूटी थी रोगी की काया देखकर, बूढ़े बैल की पिटाई देखकर, जमीन पर घिसटते हुए बुढ़ापे को देखकर और कंधे पर लदे शव को देखकर।

इन घटनाओं ने बुद्ध को भीतर तक आहत कर दिया। उन्होंने अनुभव किया, 'दुनिया में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं, वह महासागर के जल से भी कहीं अधिक है।' करुणा के बगैर मानवीय वृत्तियों पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। अहिंसा, प्रेम, दान, दया आदि गुणों का अपना कोई अर्थ नहीं है। जब वे करुणा की कोख से जन्म लेते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। करुणा और अहिंसा में फर्क है। करुणा सकारात्मक सोच है। करुणा का अर्थ है किसी के दुख-दर्द में सक्रिय रूप से भागीदार बनना। यदि किसी के रास्ते में कांटे बिछे हैं तो कारुणिक व्यक्ति सहज भाव से उसे हटाएगा, परंतु अहिंसक व्यक्ति किसी के रास्ते में कांटें नहीं बिछाएगा। बस, इतने से ही वह संतुष्ट हो जाएगा। प्रेम और करुणा में फर्क है। एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, परंतु उस पर मालिकाना हक कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। मालिक होना भी दुख का कारण है। प्रेम तो है, करुणा नहीं है। प्रेम में सुख है, करुणा में पीड़ा। प्रेम में रस है, करुणा में रिसता हुआ घाव। प्रेम फूल है, करुणा कांटों की चुभन। करुणा की कोख से जन्म लेकर अहिंसा सकारात्मक बनती है, दया निरहंकारी बनती है और प्रेम मुक्तिदायी बनता है।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

जातिवाद का बढ़ता प्रदूषण

जातिवादी राजनीति का जहर शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने जाति और संप्रदायवाद की जिस विभाजनकारी राजनीति को देश और समाज को कमजोर करने वाला बताया है, दुर्भाग्यवश वही विकृत राजनीति स्वतंत्र भारत में राजनेताओं के लिए सत्ता प्राप्त करने का सहज मार्ग बन गई। इन नेताओं के लिए सत्ता पर काबिज होने के बाद देश या प्रदेश के समुचित विकास से पहले अपनी जाति के साथ-साथ स्वयं का आर्थिक विकास करना ही मुख्य राजनीतिक उद्देश्य बन गया। ऐसे में कभी लोहिया के समाजवाद को लेकर पिछड़े वर्ग की खोखली समाजवादी राजनीति को हवा दी गई तो कभी डॉ. अंबेडकर के सामाजिक-न्याय की ओट में दलितों को सवर्णों के मनुवाद से सावधान रहने को उकसाया गया। इस तरह की विकृत राजनीति करने वाले राजनेता बेशक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों पर काबिज होकर देश की केंद्रीय राजनीति तक को प्रभावित करने में सफल हो गए हों, लेकिन अंततोगत्वा जातिवाद के इस प्रदूषण से देश के विकास को जो आघात पहुंचा है, उसकी भरपाई करना फिलहाल संभव नहीं है। आज विभिन्न जातियों के प्रमुख झंडाबरदार नेताओं के स्व-विकास को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आय से अधिक संपत्ति या बेनामी संपत्ति के मामले में ये राजनेता अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि लोहिया और अंबेडकर के सिद्धांतों को ताक पर रखने वाली इस विकृत जातिवादी राजनीति से क्या किसी राष्ट्र के समेकित विकास की कल्पना की जा सकती है?

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

कैसा स्वराज

समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में एक से एक नामचीन हस्तियां जुड़ीं। जनता ने इस आंदोलन को सर आंखो पर बिठाया। कंपनियों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे दी, ताकि वो आंदोलन में भाग ले सकें। रिक्शे वाले, आटो वाले सबने इस आंदोलन में सहयोग किया। कोई मुफ्त में पानी बांट रहा था तो कोई खाने का अन्य सामान। इसके फलस्वरूप आम आदमी पार्टी का गठन होता है। स्वराज की बात करने वाली इस पार्टी ने लोगों से पूछ कर प्रत्याशी चयन की बात की थी। अब राज्यसभा के लिए ऐसे उम्मीदवार बनाए हैं जिस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

babitakumari983@gmail.com

समाज सेवा

देश में किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए उम्मीदवार को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक बार विधायक या सांसद बनने के बाद से लेकर हारने तक भी वो सभी लाभ चाहिए जो वह पहले भोग चुके होते हैं ऐसा क्यों? यह एक व्यवसाय नहीं समाज सेवा है जिसे बिना स्वार्थ के करना चाहिए। नियम कानून सभी के लिए एक होने चाहिए।

आचार्य रामकुमार बघेल, पलवल

समभाव दिवस

दिनांक 6 जनवरी के अंक में बद्रीनारायण का लेख, अतीत के लिए भविष्य से खिलवाड़, पढ़ा। अंग्रेजो के समय में पुलिस में भी भारतीय थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भारतीयों पर लाठीचार्ज किया होगा और जेल में भी डाला होगा, लेकिन अब वह सब न किसी के लिए शर्म की बात है न गर्व की। इसी तरह कुछ भारतीय अंग्रेजी सेना में भी रहे होंगे और उस समय के काम को अंजाम दिया होगा। वह सारी बातें अतीत की हो गईं। आज के समय में महराष्ट्र की पुलिस में महार भी होंगे और मराठा भी, इसलिए सब कुछ भुलाकर इस दिन को समभाव दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।

shivssa&ena@gmail.com

छोटे जोत में कृषि कल्याण

कृषि और किसान कल्याण को लेकर ठोस रणनीति की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले 86 प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों की बात आती है, जो लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। यदि भारतीय परिदृश्य में कृषि एवं किसान का कल्याण सुनिश्चित करना है तो इन्हीं 86 प्रतिशत किसानों को ध्यान में रखकर रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करनी होगी। इस दिशा में सबसे पहले बीज वितरण प्रणाली, सिंचाई सुविधा, वित्तीय सहायता, बाजार व्यवस्था, भंडारण सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लघु एवं सीमांत जोत को ध्यान में रखकर नीति बनानी होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सक्षम किसान आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था खुद कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कमजोर और संसाधन विहीन किसान पीछे छूट जाते हैं। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले परंपरागत कृषि उत्पादन की जगह नगदी फसल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। फसल की प्राथमिकता तैयार करते समय देश-दुनिया की जरूरतों के साथ मौजूदा परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्य योजना आगे बढ़ानी होगी। इन सभी विषयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कृषि उत्पाद खरीद व्यवस्था को सशक्त और प्रभावी बनाना, जो किसानों के हितों का पूरा ख्याल रख सके। कृषि उत्पाद की खरीदारी व्यवस्था को नियमित करते समय सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। तमाम प्रयोग समस्या को दूर करने की दिशा में सफल साबित नहीं हुए हैं। सरकार कृषि उत्पाद खरीद प्रक्रिया पर सशक्त तरीके से प्राथमिकता देते हुए, विदेशी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर सकती है, जिसमें किसानों का संपूर्ण कल्याण सुनिश्चित हो।

sumitkumarjha910@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

विश्व पुस्तक मेले के दौर में यही कहूंगा कि हरेक को खुद को इंडिया का ही नहीं, दुनिया का ही नहीं, ब्रह्मांड का महानतम लेखक मानने का हक है। बस प्लीज यही बात दूसरों से मनवाने के लिए फौजदारी ना करें।

आलोक पुराणिक@puranikalok

मैं भारत में अल्पसंख्यक हूं। मुझे आरक्षण चाहिए। आबादी में हमारी हिस्सेदारी महज 2.53 फीसद है। मैं असल में भारतीय करदाता हूं।

सुनील जैन@thesuniljain

टैक्स बाबू चाहते हैं कि सोलर पैनल को भी इलेक्ट्रिक मोटर्स और जेनरेटर्स की श्रेणी में डाल दिया जाए जिससे उन पर 7.5 फीसद ड्यूटी लगे। इससे पैनल की महंगी कीमतों के चलते वे बंदरगाहों पर पड़े हैं और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्ष